

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1442

बुधवार, 12 मार्च, 2025 (21 फाल्गुन, 1946 (शक)) को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय डेटाबेस में सहकारी समितियों को शामिल करना

1442: श्री रामभाई हरजीभाई मोकिरया

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में कितनी सहकारी समितियां शामिल की गई है;
- (ख) क्या यह प्रक्रिया सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में समान रूप से अपनाई गई है; और
- (ग) उन क्षेत्रों में इस डेटाबेस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जहां सहकारी समितियां अच्छी स्थिति में नहीं हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सहयोग से एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) विकसित किया गया है। यह डेटाबेस देश भर में 8.25 लाख से अधिक सहकारी समितियों पर प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी तक एकल-बिंदु पहुँच प्रदान करता है। एनसीडी के अनुसार, 01-01-2025 से 01-03-2025 तक अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों की संख्या **1349** है। उक्त अवधि के दौरान पंजीकृत सहकारी समितियों की राज्यवार संख्या **अनुलग्नक-1** में संलग्न है।

(ख) जी महोदय, केंद्र सरकार (सहकारिता मंत्रालय) समग्र रूपरेखा और दिशानिर्देश प्रदान करती है, जबकि इस उद्देश्य के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों द्वारा डेटाबेस में सभी सहकारी समितियों के डेटा को एकत्रित, दर्ज एवं अद्यतन किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय डेटाबेस यूआरएल: <https://cooperatives.gov.in> पर सुलभ उपलब्ध है। इस डेटाबेस का इस्तेमाल नीति निर्माताओं द्वारा सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां समितियां खराब प्रदर्शन कर रही हैं। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस स्थान, सदस्यता, आर्थिक गतिविधियों और लिंकेज जैसे मापदंडों पर डेटा एकत्र करता है, जिससे सहकारी समितियों के भौगोलिक प्रसार में अंतराल की पहचान करने में मदद मिलती है, जिसमें कवर की गई और कवर नहीं की गई ग्राम पंचायतें दोनों शामिल हैं।

01-01-2025 से 01-03-2025 तक अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत पंजीकृत

सहकारी समितियों की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य	समितियों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1
2	आंध्र प्रदेश	0
3	अरुणाचल प्रदेश	3
4	असम	79
5	बिहार	523
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ़	179
8	दिल्ली	0
9	गोवा	4
10	गुजरात	53
11	हरियाणा	40
12	हिमाचल प्रदेश	67
13	जम्मू और कश्मीर	58
14	झारखंड	24
15	कर्नाटक	28
16	केरल	6
17	लद्दाख	1
18	लक्षद्वीप	1
19	मध्य प्रदेश	74
20	महाराष्ट्र	29
21	मणिपुर	0
22	मेघालय	9
23	मिजोरम	0
24	नगालैंड	0
25	ओडिशा	0
26	पुदुचेरी	0
27	पंजाब	3
28	राजस्थान	13
29	सिक्किम	0
30	तमिलनाडु	2
31	तेलंगाना	0
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0
33	त्रिपुरा	48
34	उत्तर प्रदेश	49
35	उत्तराखंड	47
36	पश्चिम बंगाल	8
	कुल	1349

स्रोत: राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल।